>

Title: Need to restart the National Development Projects in urban slum areas especially in the Rajgarh Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि भारत सरकार से पूर्व में एनएसडीपी (राष्ट्रीय गंदी बस्ती उन्मूलन योजना) के माध्यम से गंदी एवं पिछड़ी बस्तियों के विकास हेतु शहरी विकास मंत्रालय से नियमित बजट राज्यों को मिलता था। जिससे संबंधित शहरों व नगरीय क्षेत्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का त्वरित विकास होता था। केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को बंद करके इस योजना के स्थान पर आईएसएचडीपी (एकीकृत मलिन बस्ती आवास योजना) प्रारम्भ की गई है, यह भी एक अच्छी योजना है। लेकिन इस योजना के स्वीकृत होने की जो प्रक्रिया है, उसमें काफी लम्बा समय लगता है। डीपीआर तैयार होकर स्वीकृति प्रस्ताव आने में ही कई महीने लग जाते हैं।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से इस संबंध में अनुरोध है कि यह योजना अपनी जगह काम करती रहे, लेकिन एनएसडीपी (राष्ट्रीय गंदी बस्ती उन्मूलन योजना) के तहत् शहरी क्षेत्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के त्वरित निराकरण के लिए सरकार से पूर्व की भांति नियमित बजट संबंधित जिले के कलेक्टर (शहरी विकास) को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे कि गंदी एवं पिछड़ी बस्तियों का सतत् विकास जारी रहे।

अंत में मैं अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत राजगढ़, सारंगपुर सहित अन्य उन नगरीय निकायों की जल आवर्धन संबंधी योजना एवं यूआईडीएसएसएमटी तथा आईएसएचडीपी के काफी समय से लम्बित प्रस्तावों को अविलम्ब स्वीकृति के लिए भी सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह उन लम्बित प्रस्तावित योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदया:

श्री पी.एल. पुनिया और

श्री कमल किशोर कमांडो श्री नारायणसिंह अमलाबे जी के साथ अपने को सम्बद्ध करते हैं।